

वन हेल्थ

//

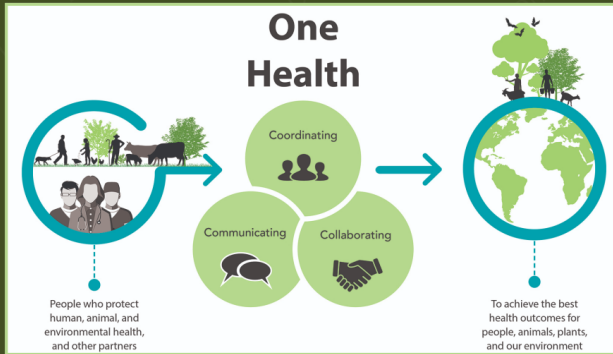
वन हेल्थ ONE HEALTH

वन हेल्थ ट्राई पार्टी अलायन्स यानी FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE)

WHO के बीव समझौते के आधार पर गतिविधियों का एक सेट प्रदान करता है जिसका उद्देश्य मानव-पशु-पौधे-पर्यावरण इंटरफेस से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना है।

दृष्टिकोण

- मानवों और लोगों में जूनोटिक रोग के प्रकोप को रोकना
- स्वाद्य सुरक्षा में सुधार
- MMR संक्रमण को कम करना और मानव तथा पशु स्वास्थ्य में सुधार करना
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार करना
- नैव विविधता की रक्षा और संरक्षण



वन हेल्थ से संबंधित तथ्य

- मानव रोगों का कारण बनने वाले 60% रोगजनक, घरेलू पशुओं या वन्यजीवों से उत्पन्न होते हैं
- वैश्विक पशु उत्पादन में 20% की गिरावट पशु रोगों से जुड़ी हुई है
- जब मूल वन आवरण का 25% से अधिक नष्ट हो जाता है तो मनुष्यों और उनके पशुओं की वन्यजीवों से सामना करने की संभावना अधिक होती है

वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना

- स्वाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा एक नई चतुष्पक्षी पहल
- यह योजना वर्ष 2022-2026 तक वैध है और इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करना है।

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM)

NOHM

- इसका उद्देश्य मानव और पशु दोनों क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली बीमारियों के विरुद्ध समग्र महामारी की तैयारी और एकीकृत रोग नियंत्रण को प्राप्त करने के लिये समन्वय करना है

हाल ही में उठाए गए कदम

- पशु महामारी तैयार पहल (APPI)
- वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (AHSSOH)

पूर्व में की गई पहलें

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, 2004
- बूनोब से निपटने के लिये एक बहु-विषयक रोड मैप (2008)

घटक



रिट (W R I T S)



Drishti IAS

रिट के प्रकार	उद्देश्य	जिनके विरुद्ध जारी की जा सकती है	जिनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	अवैध मामले के लिये हिरासत में लिये गए व्यक्ति को छोड़ने का निर्देश देना	A. सार्वजनिक प्राधिकरणों B. निजी व्यक्तियों	A. निवारक निरोध B. न्यायालय/विधायिका की अवमानना से संबंधित कार्रवाई C. न्यायालय के न्यायाधिक क्षेत्र के बाहर हिरासत
परमादेश (Mandamus)	एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य करने के लिये निर्देशित करना	A. सार्वजनिक निकाय B. निगम C. एक अवैध न्यायालय D. ट्रिब्यूनल E. सरकार	A. निजी व्यक्ति/निकाय B. जब विवेकानुसार कर्तव्य हो C. संविदात्मक दायित्व D. राष्ट्रपति, राज्यपाल E. CJI, HC की न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे CJ
अधिकार पृच्छा (Qua Warranto)	अवैध तरीके से ग्रहण किये गए पद को रिवक्त करने के लिये किसी व्यक्ति को निर्देशित करना	केवल न्यायिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध	प्रशासनिक, विधायी और निजी निकाय तथा व्यक्ति
प्रतिषेध (Prohibition)	अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले पर कार्रवाई करने से रोकना	न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध	विधायी और निजी निकाय तथा व्यक्ति
उत्प्रेषण (Certiorari)	एक उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई से हटा देता है और इसे अपने समक्ष ले आता है	केवल एक वैधानिक/संवैधानिक सार्वजनिक कार्यालय	A. मंत्रालयी कार्यालय B. निजी कार्यालय

संवैधानिक प्रावधान

■ अनुच्छेद 32:

- SC रिट जारी कर सकता है
- संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है (हालाँकि, अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है)

अनुच्छेद 32 के तहत, SC को मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटीकर्ता के रूप में स्थापित किया गया है

■ अनुच्छेद 226:

- HCs रिट जारी कर सकते हैं

1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के HCs के पास रिट जारी करने की शक्ति थी

रिट क्षेत्राधिकार

विशेषताएँ	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
रिट जारी करने का उद्देश्य	केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये	कानूनी के साथ-साथ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये
किसी व्यक्ति/सरकार के विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है	भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी	केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर स्थित क्षेत्र में या यदि कार्रवाई उसके क्षेत्रीय अधिकार वाले क्षेत्र में घटित होती है
रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मनाही का अधिकार	क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक FR है इसलिए मनाही का विकल्प नहीं है	अनुच्छेद 226 के तहत उपचार के रूप में मनाही विवेकाधीन है

पशु महामारी तैयारी पहल और “वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता”

प्रलिमिन्स के लिये:

[वन हेल्थ दृष्टिकोण](#), WHO, [वर्ल्ड बैंक](#), [ज़ूनोटिक रोग](#)

मेन्स के लिये:

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के खतरे को रोकने के लिये वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत पशु महामारी तैयारी पहल (Animal Pandemic Preparedness Initiative- APPI) शुरू की है।

- वन हेल्थ दृष्टिकोण पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डालता है।
- मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एनमिल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ (AHSSOH) परियोजना भी शुरू की है।

पशु महामारी तैयारी पहल:

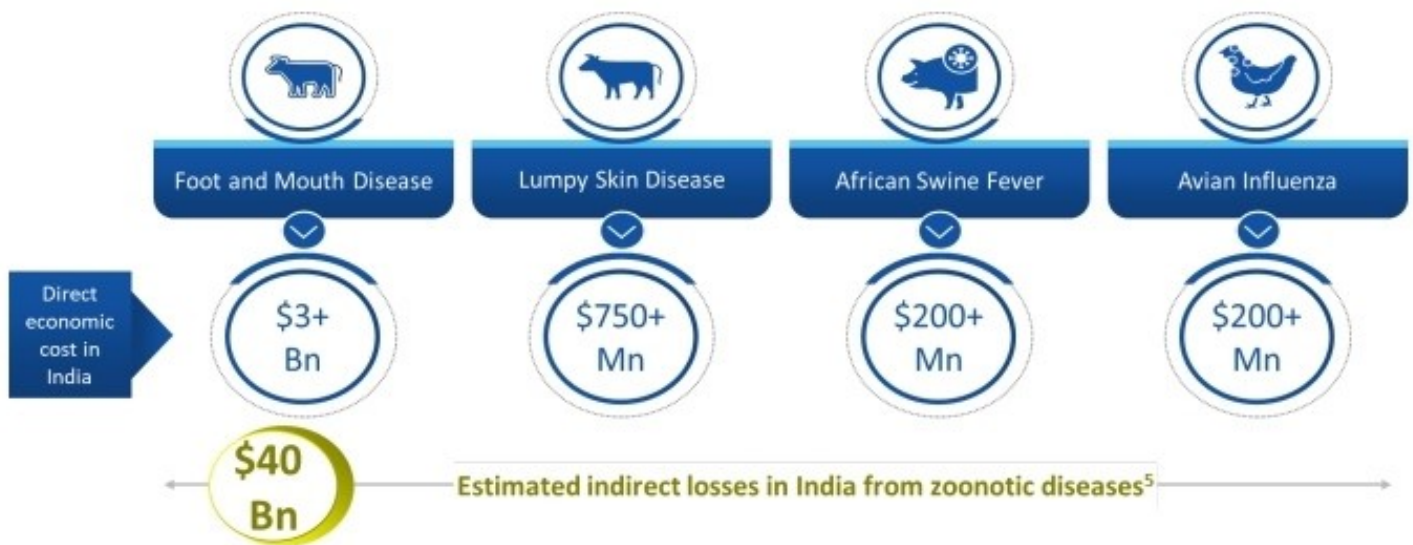
- **परिचय:**
 - यह पहल [विश्व स्वास्थ्य संगठन](#) की ग्लोबल वन हेल्थ रणनीतिके अनुरूप है, जो जूनोटिक रोगों के खतरे को दूर करने में बहुक्षेत्रीय सहयोग पर जोर देती है।
 - यह पशु चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढाँचे, रोग निगरानी क्षमताओं, शीघ्र पहचान एवं प्रतिक्रिया, पशु स्वास्थ्य पेशेवरों की क्षमता का निर्माण तथा सामुदायिक पहुँच के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी।
- **APPI के स्तंभ:**
 - रोग निगरानी और नयितरण।
 - रोग मॉडल एल्गोरिदम और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
 - प्रकोप जाँच और प्रतिक्रिया।
 - पारस्थितिक तंत्र समन्वय।
 - टीका विकास और अनुसंधान तथा विकास।
 - आपदा प्रतिक्रिया का निर्माण।
 - अनुदान।
 - नियामक ढाँचा।
- **उद्देश्य:**
 - इस पहल का उद्देश्य जूनोटिक रोगों को रोकने और नयितरति करने के लिये भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है, ताकि जानवरों तथा मनुष्यों दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (AHSSOH):

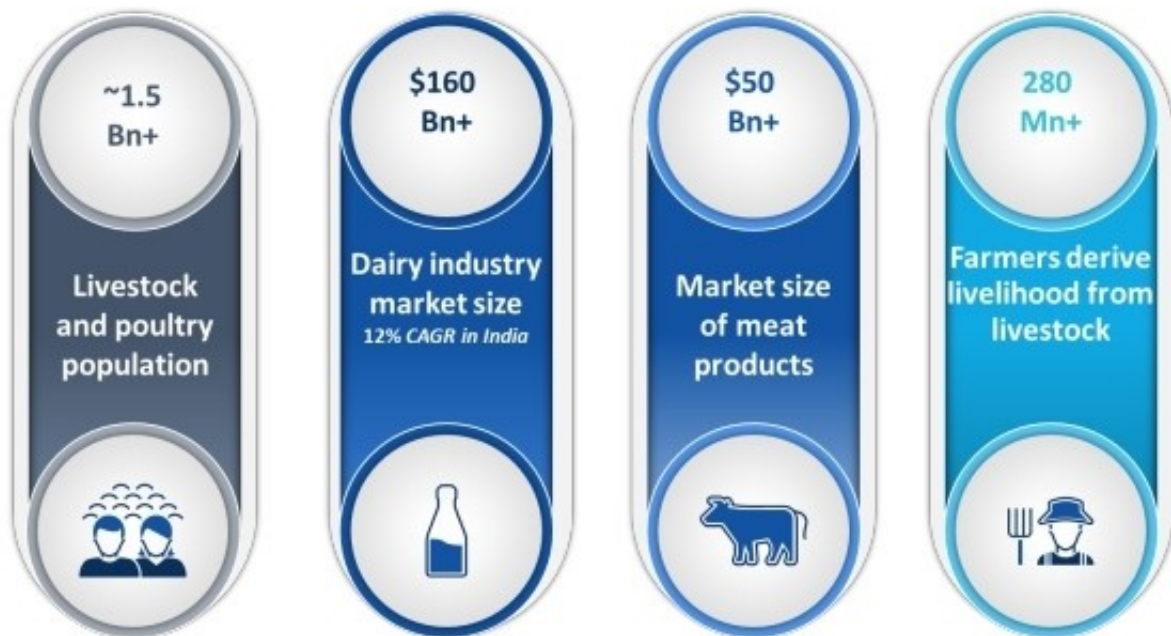
- इसका उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण (One Health Approach) को ध्यान में रखकर बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिये एक पारस्थितिक तंत्र बनाना है।
- परियोजना को [केंद्रीय क्षेत्र योजना](#) के रूप में पाँच साल की अवधि हेतु लागू किया जाएगा।
- इसमें भाग लेने वाले पाँच राज्यों के 151 जिलों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जसमें 75 जिला/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के साथ-साथ 300 पशु चिकित्सालयों/औषधालयों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पशुधन रोग दबाव और पशुधन क्षेत्र का परिदृश्य (Scenario of Livestock Diseases Burden and Livestock Sector)

Livestock Disease Burden



Indian Livestock Sector



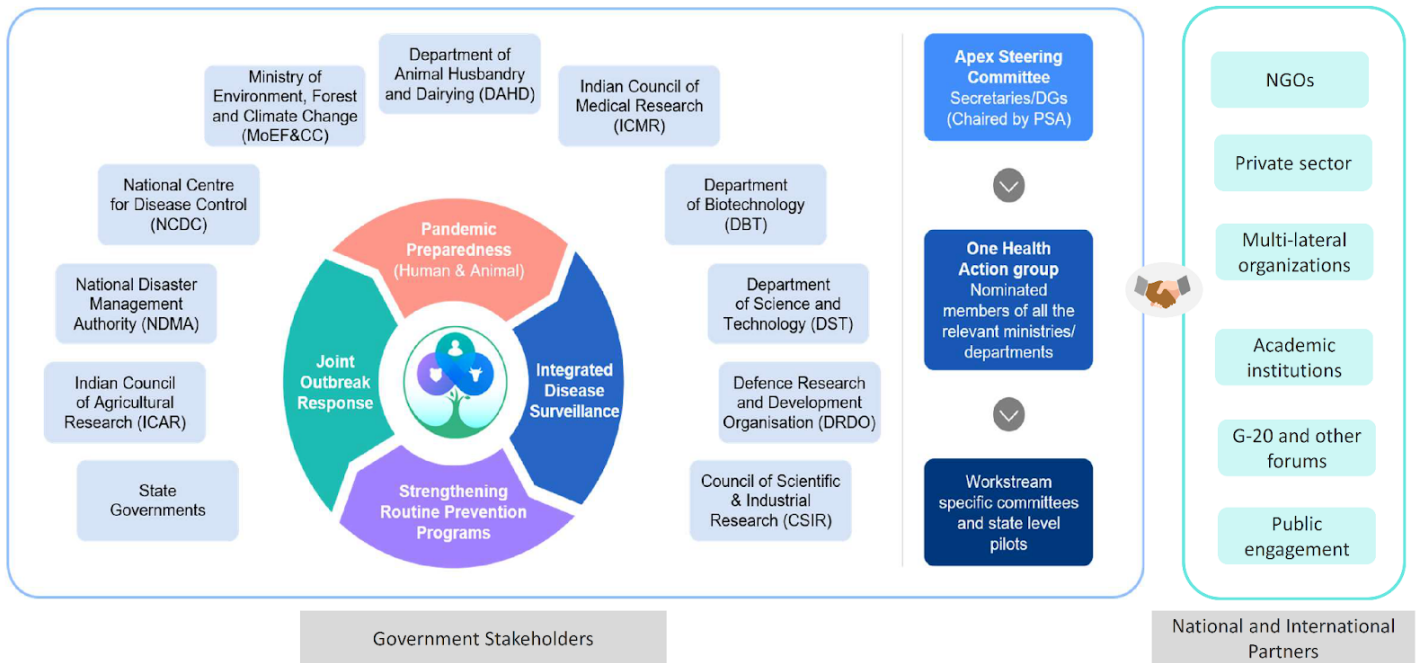
राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (National One Health Mission- NOHM):

■ वन हेल्थ:

- वन हेल्थ (One Health) के तहत **स्वास्थ्य, उत्पादकता और संरक्षण** चुनौतियों को हल करने हेतु **वभिन्न क्षेत्रों बीच समन्वय सुनिश्चित करना** है, जो भारत के विविध **वन्य जीवन, बड़ी पशुधन आबादी और उच्च मानव घनत्व** के लिये महत्वपूर्ण है।
- कोविड-19, गाँठदार त्वचा रोग और एवयिन इन्फ्लूएंजा** (Avian influenza-AI) जैसे हाल के रोग प्रकोपों से पता चलता है कि केवल मानवीय दृष्टिकोण से बीमारी को संबोधित करना पर्याप्त नहीं है। हमें पशुधन और वन्य जीवन पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

परिचय:

- NOHM, प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) की 21वीं बैठक में अनुमोदित अंतर-मंत्रालयी प्रयास है।
- NOHM को अन्य मंत्रालयों के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।



उद्देश्य:

- NOHM रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिये समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु मानव, पशु तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अन्यायपूर्णता को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसका उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अन्यायपूर्णता को उजागर करते हुए भारत में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु एक समन्वित तथा एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

घटक:

- जूनोटिक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध हेतु निगरानी एवं [पूर्व चेतावनी प्रणाली \(Early Warning Systems\)](#) को मजबूत करना।
- वन हेल्थ क्षेत्र में [अनुसंधान और विकास](#) को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य पेशेवरों, पशु चिकित्सकों और शोधकर्ताओं की क्षमता निर्माण में सुधार।
- वन हेल्थ के मुद्दों पर [जन जागरूकता और सामुदायिक](#) जुड़ाव बढ़ाना।
- वन हेल्थ हस्तक्षेप और रणनीतियों हेतु दिशा-निर्देश एवं नीतियाँ विकसित करना।
- [वन हेल्थ डेटा रपिडिटी और सूचना प्रणाली](#) की स्थापना।
- वन हेल्थ चुनौतियों का समाधान करने हेतु [राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं साझेदारी](#) को सुगम बनाना।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

डिजिटल हेल्थ समिति 2023

प्रलम्ब के लिये:

मेन्स के लयि:

भारत में डजिटल हेल्थकेयर से संबंधति मुद्दे, डजिटल स्वास्थय से संबंधति प्रमुख सरकारी पहल

चरचा में क्यो?

हाल ही में गोवा में [भारतीय उद्योग परसिंघ](#) (Confederation of Indian Industry- CII) द्वारा [डजिटल हेल्थ समिति 2023](#) का आयोजन किया गया ।

- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-आधारति और उद्योग-प्रबंधति संगठन है ।

डजिटल हेल्थ समिति 2023 की प्रमुख वशिषताएँ:

- इसने [डजिटल स्वास्थय](#) नवाचारों के महत्त्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे वे [3D प्ररटिगि](#), पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स, रोबोट, [जैव सूचना वजिज्ञान](#) तथा जीनोमिक्स सहति घातीय चकितिसा को सशक्त बना सकते हैं ।
- इसका उद्देश्य [अंतरसंचालनीयता](#), [डेटा गोपनीयता](#) और [डेटा सुरक्षा](#) मानकों को बढ़ावा देने के लयि एक डजिटल पब्लिक गुड्स फ्रेमवरक बनाना है ।
- इसने उच्च गुणवत्तापूर्ण चकितिसा तक समान पहुँच के साथ "नागरिक केंद्रति" डजिटल स्वास्थय प्रणालयों की आवश्यकता पर बल दिया ।
- साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाला कि स्वास्थय प्रौद्योगिकी [चौथी औद्योगिक क्रांति](#) का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है ।

डजिटल स्वास्थय देखभाल:

- **परचिय:**
 - डजिटल स्वास्थय सेवा [चकितिसा देखभाल वतिरण](#) की एक प्रणाली है जो गुणवत्तापूर्ण चकितिसा देखभाल सेवाओं को सुलभ, सस्ती और टकिारु बनाने के लयि [डजिटल तकनीकों](#) की एक शृंखला का उपयोग करती है ।
 - डजिटल स्वास्थय के व्यापक दायरे में [मोबाइल स्वास्थय \(mHealth\)](#), [स्वास्थय सूचना प्रौद्योगिकी \(IT\)](#), पहनने योग्य उपकरण, [टेलीहेल्थ](#) और [टेलीमेडसिनि](#) और व्यक्तगित चकितिसा जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं ।
 - [वशि्व स्वास्थय सभा \(World Health Assembly\)](#) द्वारा वर्ष 2020 में अपनाई गई [डजिटल स्वास्थय पर WHO की वैश्विक रणनीति](#), नवाचार और डजिटल स्वास्थय में नवीनतम विकास को शामिल करने के लयि एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य स्वास्थय परिणामों में सुधार हेतु इन उपकरणों का उपयोग करना है ।
- **प्रमुख अनुप्रयोग:**
 - [पवाइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स](#): पवाइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक्स ("POCD") चकितिसा उपकरण उद्योग में एक उभरती हुई प्रवृत्ति है और इसमें उत्पादों की एक वसितृत शृंखला शामिल है जो रोगियों या स्वास्थय देखभाल चकितिसकों द्वारा संसाधन सीमति समायोजन द्वारा सटीक नदिन में सक्षम बनाती है ।
 - हाल के दनिों में [बायोसेंसर](#), [पोर्टेबल एक्स रे](#), [हैडहेल्ड अल्ट्रासाउंड](#) और [स्मार्टफोन आधारति POCD](#) जैसे कई [एप्लीकेशन वकिसति कयि गए हैं](#) ।
 - [चकितिसा आभासी सहायक](#): आभासी स्वास्थय सहायक और चैटबॉट रोगियों तथा चकितिसकों के बीच के अंतराल को भरते हैं तथा [नयुक्तिनिर्धारण](#), [स्वास्थय रकिॉर्ड बनाए रखने](#) एवं अन्य प्रशासनकि कार्यों जैसी सेवाओं के माध्यम से रोगियों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं ।
 - [स्व-नगिरानी हेल्थकेयर डविाइस](#): मॉनटिर और सेंसर अब पहनने योग्य उपकरणों में एकीकृत कयि जा रहे हैं, जो इन्हें शरीर में वभिनिन शारीरिक परिवर्तनों का पता लगाने की अनुमतति देते हैं ।
 - ये स्मार्ट डविाइस वज़न, नींद के पैटर्न, आसन, आहार और व्यायाम को ट्रैक करने में सक्षम हैं ।
 - [ई-फारमेसी](#): ई-फारमेसी एक ऐसी फारमेसी है जो इंटरनेट के माध्यम से कार्य करती है और मेल, कूरयिर या डिलीवरी परसन के माध्यम से [ऑर्डर का नपिटान सुनशिचति करती है](#) ।
- **डजिटल हेल्थकेयर के लाभ:**
 - [टेलीमेडसिनि](#) ने [स्वास्थय सेवा के वकिेंद्रीकरण](#) और दूरस्थ तथा उन्नत देखभाल तक पहुँच सुनशिचति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
 - ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों के मरीज़ अब ऑनलाइन परामर्श और दवाओं की होम डिलीवरी के माध्यम से सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण [स्वास्थय सेवा](#) प्राप्त कर सकते हैं ।
 - डजिटल उपकरण स्वास्थय सेवा प्रदाताओं को [स्वास्थय डेटा तक पहुँच प्रदान कर रोगी के स्वास्थय के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं](#) ।

भारत में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चुनौतियाँ:

- **परिचय:**
- भारत ने [कोविड-19 महामारी](#) को देखते हुए तीव्र गति से डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाया है। इस अभूतपूर्व [स्वास्थ्य संकट](#) ने टेलीमेडिसिन को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रकार भारत में दूरस्थ तथा रोगी-केंद्रित देखभाल की शुरुआत हुई।
- **चुनौतियाँ:**
 - स्पष्ट वनियमों की अनुपस्थिति: स्पष्ट वनियमों और दशि-नरिदेशों के अभाव में दुरुव्यवहार, स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड का दुरुपयोग, डेटा चोरी तथा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का दुरुपयोग हो सकता है।
 - साथ ही डिजिटल बुनियादी ढाँचे एवं कुशल पेशेवरों की कमी भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के डिजिटलीकरण हेतु एक और बाधा है।
 - डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा: डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में रोगी का विश्वास बनाए रखने हेतु डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। सुरक्षा उपायों की कमी से डेटा का उल्लंघन हो सकता है तथा रोगी के डेटा से समझौता हो सकता है।
 - उदाहरण: हाल ही में [AIIMS दिल्ली में रैनसमवेयर हमले की घटना](#) हुई।
 - ई-फार्मेसी को वैधानिक समर्थन नहीं: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 भारत में दवाओं के आयात, निर्माण एवं वितरण को नियंत्रित करता है।
 - हालाँकि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 या फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत "ई-फार्मेसी" की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी पहल:**
 - आयुष्मान भारत डिजिटल मशिन (ABDM).
 - ई-संजीवनी टेलीकंसलटेशन सर्विस
 - आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
 - कोविन एप

डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु WHO के उद्देश्य:

- अंतर-संचालनीयता और डेटा शेयरिंग के लिये मानकों के निर्धारण के माध्यम से डेटा, अनुसंधान एवं साक्ष्य सुनिश्चित करना तथा सूचित नरिणय लेने के लिये डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन का समर्थन करना।
- नई तकनीक द्वारा समर्थित अभ्यास में वैज्ञानिक समुदायों का उपयोग करके ज्ञान बढ़ाना और विशेषज्ञ दृष्टिकोण के बीच नैदानिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों की चर्चा को सुविधाजनक बनाना।
- देश की जरूरतों के आधार पर नवाचारों की पहचान, प्रचार, सह-विकास और वृद्धि के लिये एक सक्रिय रणनीति अपनाना। इसके तहत किसी देश के नवाचारों के माध्यम से जरूरतों एवं आपूर्ति के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

आगे की राह

- **AI पावरड हेल्थकेयर:** बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण, जाँच करने के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र में [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#) का तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है।
 - इस तकनीक में लागत कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण की सटीकता और गति में सुधार करने की क्षमता है।
- **हेल्थकेयर में ब्लॉकचेन:** ब्लॉकचेन तकनीक स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता में सुधार करने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं को कारगर बनाने में मदद कर सकती है।
 - ब्लॉकचेन सूचनाओं को संगृहीत और साझा करने के लिये एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीका प्रदान करता है, इससे त्रुटियों, धोखाधड़ी एवं प्रशासनिक लागतों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **मोबाइल हेल्थ (mHealth):** mHealth के अंतर्गत अप्रत्यक्ष तौर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये मोबाइल उपकरणों और एप्स का उपयोग करना शामिल है।
 - यह विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा तक सीमिति पहुँच वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। mHealth रोगियों को पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करने और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अधिक आसानी से सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद कर सकता है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

आपराधिक जाँच में आवाज़ के नमूने

प्रलिमिस के लिये:

आपराधिक जाँच में आवाज़ के नमूने, [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो](#), [नजिता का अधिकार](#) ।

मेन्स के लिये:

आपराधिक जाँच में आवाज़ पहचान तकनीक की विश्वसनीयता और सटीकता, न्यायालय में सबूत के रूप में आवाज़ के नमूने के उपयोग संबंधी कानूनी और नैतिक विचार ।

चर्चा में क्यों?

वर्ष 1984 के सखि वसिंधी दंगों में कथित संलग्नता के संबंध में हाल ही में एक राजनेता को एक विशेष भाषण की पुष्टि हेतु अपनी आवाज़ के नमूने प्रस्तुत करने के लिये [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो](#) के समक्ष उपस्थिति होना पड़ा ।

- आवाज़ के नमूने **आपराधिक जाँच में महत्वपूर्ण स्रोत बन** गए हैं, जिससे जाँचकर्ताओं को सबूतों की पुष्टि करने एवं संदिग्धों की पहचान करने की अनुमति मिलती है ।

आवाज़ के नमूने प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- **प्रक्रिया:**
 - जाँच एजेंसियाँ किसी व्यक्ति की आवाज़ का नमूना लेने के लिये न्यायालय की अनुमति लेती हैं । **आवाज़ का नमूना लेने का कार्य एक नयित्व और शोर-मुक्त वातावरण में किया जाता है ।**
 - नमूना रिकॉर्ड करने के लिये वॉयस रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है जिसमें संबद्ध व्यक्ति से उसके **बयान के हिससे के किसी विशिष्ट शब्द को बोलने के लिये कहा जाता है जो पहले से ही साक्ष्य का हिस्सा होता है ।**
- **तुलना की विधि:**
 - पाँच संदिग्ध लोगों और एक अज्ञात आवाज़ के नमूने की तुलना की जाती है; वक्ता की पहचान के साथ ही दोनों आवाज़ के नमूनों की पुष्टि होती जाती है ।
 - आवाज़ रिकॉर्ड करने हेतु अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक अक्षरों का उपयोग किया जाता है जिसमें वषिय के मूल कथन का केवल एक छोटा सा हिस्सा (वर्णिलेखन में आसानी हेतु) उच्चारित किया जाता है ।
 - **भारत में आवाज़ का नमूना लेने की प्रक्रिया:**
 - भारतीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में आवाज़ के नमूने की **सेमी-ऑटोमैटिक स्पेक्ट्रोग्राफिक पद्धति का उपयोग किया जाता है ।**
 - फोरेंसिक लेब जाँच एजेंसी को अंतिम रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें बताया जाता है कि आवाज़ के नमूने के विश्लेषण के परिणाम सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक ।
 - हालाँकि कुछ देशों में स्वचालित पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें आवाज़ के नमूनों को संभावित अनुपात में विकसित किया जाता है । इससे दक्षता बढ़ती है ।
- **कमियाँ:**
 - यदि **दवाओं के प्रभाव के कारण व्यक्ति की आवाज़ बदल** जाती है या यदि व्यक्ति **सिंरी से पीड़ित** है तो परिणाम में **अशुद्ध उत्पन्न** हो सकती है ।
 - इस नमूने की विश्वसनीयता **विशेषज्ञ द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक** और न्यायालय द्वारा इसका विश्लेषण करने के तरीके पर निर्भर करती है ।

आवाज़ के नमूने एकत्र करने की वैधता:

- वर्ष 2013 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि **आवाज़ के नमूने एकत्र करना [आत्म-अभिशंसन के खिलाफ मौलिक अधिकार](#) अथवा नजिता के अधिकार का उल्लंघन होगा या नहीं ।**
- **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 (1)** DNA विश्लेषण अथवा शरीर की सामान्य जाँच के लिये नमूने एकत्र करने हेतु पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक चिकित्सक द्वारा आरोपी की जाँच या फिर **"इस तरह के अन्य आवश्यक परीक्षण"** की अनुमति देती है ।
 - धारा 53 (1) में "ऐसे अन्य परीक्षण" वाक्यांश को आवाज़ के नमूनों के संग्रह को शामिल करने के समान है । हालाँकि आपराधिक प्रक्रिया कानूनों के तहत आवाज़ के नमूनों के परीक्षण के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं है क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत नया तकनीकी साधन है ।
 - वर्ष 2013 के मामले में एक खंडित फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि इस उद्देश्य के लिये एक विशिष्ट कानून उपलब्ध नहीं है ।
- तीन न्यायाधीशों की बेंच की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **जाँच के लिये आवाज़ का नमूना एकत्र करने से अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा ।**
 - इसने माना कि **नजिता के अधिकार को पूर्ण नहीं माना जा सकता है और इसे सार्वजनिक हित में बदला जाना चाहिये ।**

- हाल ही में वर्ष 2022 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले में यह भी पाया गया कि आवाज़ के नमूने उंगलियों के निशान एवं लिखावट से मलिते-जुलते हैं तथा कानून के अनुसार अनुमतिके साथ एकत्र किये जाते हैं और पहले से एकत्र किये गए सबूतों की तुलना करने के लिये उपयोग किये जाते हैं।

नजिता का अधिकार:

- नजिता के अधिकार को [अनुच्छेद 21](#) के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संवधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने [के.एस. पुट्टासवामी बनाम भारत संघ](#) 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में नजिता और उसके महत्व को बताया था कि नजिता का अधिकार एक मौलिक एवं अविच्छेद्य अधिकार है तथा उस व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी और उसके द्वारा चुने गए वकिलों को कवर करने वाले व्यक्ति को जोड़ता है।

पछिले मामले जहाँ आवाज़ के नमूने एकत्र किये गए:

- **भारत:**
 - आवश्यक वस्तु और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत एक विशेष अदालत ने फरवरी 2021 में [नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो \(NCB\)](#) द्वारा दायर एक याचिका को अनुमति दी थी जिसमें अभिनिता सुशांत सहि राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले में 33 अभियुक्तों की आवाज़ के नमूने एकत्र करने की मांग की गई थी।
- **अन्य देश:**
 - यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने पहली बार 1950 के दशक में वॉयस आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस की तकनीक का इस्तेमाल किया था।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. फगिरप्रटि स्कैनगि के अलावा किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान में नमिनलिखित में से कसिका उपयोग किया जा सकता है? (2014)

1. आईरसि स्कैनगि
2. रेटनिल स्कैनगि
3. आवाज़ पहचान

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- बायोमीट्रिक सत्यापन कोई भी माध्यम हो सकता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को एक या अधिक विशिष्ट जैविक लक्षणों का मूल्यांकन करके विशिष्ट रूप से पहचाना जा सकता है।
- विशिष्ट पहचानों में उंगलियों के निशान, हाथ की ज्यामिति, ईयरलॉब ज्यामिति, रेटिना और आईरसि पैटर्न, आवाज़ तरंगें, डीएनए तथा हस्ताक्षर शामिल हैं। बायोमीट्रिक सत्यापन का सबसे पुराना रूप फगिरप्रटिगि है।
- बायोमीट्रिक पहचान के लिये दी गई सभी प्रक्रियाओं, अर्थात् आईरसि स्कैन, वॉयस रकिग्नशिनि और रेटनिल स्कैनगि का उपयोग किया जा सकता है। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।
- अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

कार्बन मुक्त वदियुत उत्पादन के प्रतG7 की प्रतबिद्धता

प्रलिमिस के लिये:

G7 शखिर सम्मेलन हरिशामि, [वैश्वकि ऊरजा संकट](#), [शुद्ध-शून्य गरीनहाउस गैस \(GHG\) उत्सर्जन](#), [IPCC](#), [प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना](#), [हरति ऊरजा गलियारा](#), [राष्ट्रीय समारट ग्रडि मशिन \(NSGM\)](#)

मेन्स के लिये:

[G7](#), कार्बन-मुक्त वदियुत उत्पादन से संबंधित भारतीय पहल ।

चर्चा में क्यों?

[सात देशों के समूह \(Group of Seven- G7\)](#) के जलवायु और ऊरजा मंत्रियों तथा दूतों ने वर्ष 2035 तक [कार्बन मुक्त वदियुत उत्पादन](#) सुनिश्चित करने एवं कोयले की चरणबद्ध समाप्ति/फेज-आउट की दशा में तेज़ी लाने हेतु प्रतबिद्धता जताई है । मई 2023 में हरिशामि में आयोजित [G7 शखिर सम्मेलन](#) से पहले यह समझौता सापपोरो, जापान में कया गया था ।

- [G20 की अध्यक्षता](#) के संदर्भ में भारत को शखिर सम्मेलन में 'अतिथि' के रूप में भी आमंत्रित कया गया था ।

प्रमुख बिंदु

- मौजूदा [वैश्वकि ऊरजा संकट](#) और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए इस समझौते में वर्ष 2050 तक [शुद्ध-शून्य गरीनहाउस गैस \(Greenhouse Gas- GHG\)](#) उत्सर्जन हेतु स्वच्छ ऊरजा को अपनाने में तेज़ी लाने का आह्वान कया गया है ।
 - G7 देशों ने वर्ष 2030 तक GHG उत्सर्जन को लगभग 43% और वर्ष 2035 तक 60% कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया ।
- [IPCC की AR6 रपिरट](#) के अनुसार, जसिमें शताब्दी के अंत तक वैश्वकि तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने की आवश्यकता को इंगित कया गया है, प्रतभागी देशों ने अपतटीय प्लेटफॉर्मों से 1,000 गीगावाट सौर ऊरजा और 150 गीगावाट पवन ऊरजा का उत्पादन करने के लिये [सौर](#) एवं [पवन ऊरजा](#) क्षेत्र में निवेश में तेज़ी लाने पर सहमतवियक्त की ।
- इसमें पुष्टि की गई है कि [जीवाश्म ईंधन सब्सिडी](#) परिस समझौते के लक्ष्यों के साथ असंगत है और वे वर्ष 2025 तक अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खतम करने के लिये प्रतबिद्ध हैं ।
- वे प्रमुख मुद्दे जनि पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई:
 - अन्य देशों को उनके ऊरजा संक्रमण और ऊरजा दक्षता बढ़ाने में मदद करने के लिये और अधिक सहायता दिये जाने के संबंध में ।
 - [UNFCCC COP 27](#) में प्रतवर्ष 100 बलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की प्रतबिद्धता जताई गई थी, परंतु वकिसति देशों द्वारा कयि जाने वाले वलित्तीय योगदान में कमी आई है ।
 - ब्रिटन और कनाडा द्वारा वर्ष 2030 तक कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव ।

G7:

- परिचय:
 - सात देशों का समूह (G7) एक अंतर-सरकारी संगठन है जसिमें सात प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं ।
 - G7, मूल रूप से G8 (जब इसमें शामिल होने के लिये रूस को आमंत्रित नहीं कया गया था), को वर्ष 1975 में विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्वकर्ताओं के एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापित कया गया था ।
- उद्देश्य:
 - G7 का प्राथमिक उद्देश्य [इसके सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना](#) है ।
 - यह व्यापार, आर्थिक नीति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहित पारस्परिक चिंतीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है ।
 - [जलवायु परिवर्तन](#), [गरीबी में कमी लाना](#) और [वैश्वकि स्वास्थ्य](#) जैसे मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देता है ।
- बैठकें:
 - G7 शखिर सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कया जाता है जसिमें सदस्य देश वभिन्न मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिये एकत्रित होते हैं ।
 - इस शखिर सम्मेलन का आयोजन क्रमिक रूप से इसके सदस्य देशों द्वारा कया जाता है ।
- महत्त्व:
 - आर्थिक शक्तियाँ: G7 देश विश्व की कुछ सबसे बड़ी और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो दुनिया की 40 प्रतशित आर्थिक

- ये वैश्वक व्यापार नीतियों और वनियमों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव के साथ विश्व के अग्रणी व्यापारिक राष्ट्रों में भी शामिल हैं।
- **वैश्वक शासन:** G7 वैश्वक शासन की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है, जिसका संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है।
 - इसकी नीतियों और नरिनयों का वैश्वक आर्थिक तथा राजनीतिक स्थरिता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

- G7, जिसमें वशिव की कुछ सबसे वकिसति अरथव्यवस्थाएँ शामिल हैं, वैश्वकि कार्बन उत्सर्जन के लगभग एक-चौथाई हसिसे के लयि ज़मिमेदार है।
 - यह आश्चर्यचकति कर देने वाला आँकड़ा है जो जलवायु परविरतन के कार्यक्रम चलाने में इन देशों की महत्त्वपूर्ण भूमकि को रेखांकित करता है।
- G7 को वशिव की आबादी का वशिषिट और अपरतनिधि होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यह वैश्वकि आबादी के केवल एक छोटे से हसिसे का परतनिधित्व करता है एवं भारत तथा चीन जैसे देश इससे बाहर हैं, जो कपिरमुख आर्थकि शक्तयि हैं।
- आलोचकों ने यह भी तर्क दयिा है कि हाल के वर्षों में G7 के प्रभाव में कमी आई है क्योंकि उभरती अरथव्यवस्थाएँ वैश्वकि अरथव्यवस्था में अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।

- **प्रधानमंत्री सहज वदियुत हर घर योजना (सौभाग्य):** वशिवसनीय और ससूती बजिली तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सशक्त बनाना ।
- **ग्रनीन एनरजी कॉरडिओर (GEC):** भारत के राषट्रीय ट्रांसमशिन नेटवर्क के साथ ग्रडि से जुडी नवीकरणीय ऊर्जा को सकिरोनाइज करना ।
- **नेशनल स्मारट ग्रडि मशिन (NSGM) और स्मारट मीटर नेशनल प्रोग्राम (SMNP):** भारत के वदियुत क्षेत्तर को सुरक्षति, अनुकूली, टकिऊ व डजिटिल रूप से सक्षम आधुनकि पारसिथतिकि तंत्र बनाना ।
- **प्रदरशन, उपलबध और वयापार (PAT):** ऊर्जा प्रभावशीलता में सुधार करना और उन औदयोगकि क्षेत्तरों से उत्सर्जन को कम करना जनिहें वनियिमति करना मुशकलि है ।
- **राषट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDCs):** अदयतन NDC के अनुसार, भारत अब वरष 2005 के स्तर से वरष **2030 तक** अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को **45% तक** कम करने और वरष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारति ऊर्जा संसाधनों से लगभग **50%** संचयी वदियुत शक्ति सथापति कषमता परापत करने के लयि परतबिदध है ।

?????????:

अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड
ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम
इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया

?????:

प्रश्न. "सतत, वशिवसनीय, टकराऊ और आधुनक कूरजा तक पहुँच सतत वकलस लकष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लयल अनवलर्य है।" इस संबंघ में भारत में हई परगतपर टपरणी कीजयल। (2018)

प्रश्न. पारंपरिक ऊर्जा की समस्या को दूर करने के लिये भारत के हरति ऊर्जा गलियारे पर एक टपिपणी लखियि। (2013)

सरोतः द हृदि

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

प्रलिमिस के लिये:

मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोट, साइबर-आतंकवाद, NIA, सूचीबद्ध अपराध, आतंकवाद, LWE, उग्रवाद, कट्टरता, NIA अधिनियम 2008 ।

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसका कार्य और क्षेत्राधिकार, कट्टरता- मुद्रा, चुनौतियाँ, समाधान ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA)** ने दो लोगों के खिलाफ एक **प्राथमिकी/प्रथम सूचना रिपोर्ट** दर्ज की है, जिन्हें कथित रूप से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में गरिफ्तार किया गया था ।

- NIA ने दो लोगों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और **गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967** के तहत आरोप लगाए हैं ।

नोट: **कट्टरता** वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या समूह **चरम विश्वासों और विचारधाराओं को अपनाता है जो मुख्यधारा के समाज के मूल्यों, मानदंडों एवं कानूनों को असवीकार या विरोध करते हैं** । इसमें प्रायः प्रचार, प्रेरक बयानबाज़ी तथा प्रेरक व्यक्तियों या समूहों का जोखिम शामिल होता है जो **चरमपंथी विचारों व विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं** ।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण:

- **परिचय:**
 - NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो **आतंकवाद, उग्रवाद** और अन्य **राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों** की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़िम्मेदार है ।
 - किसी देश में संघीय एजेंसियों के पास विशेष रूप से उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, न कि केवल अलग-अलग राज्यों या प्रांतों से संबंधित होते हैं ।
 - **वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों** के बाद **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008** के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है ।
 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 में बदलाव करते हुए **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019** को जुलाई 2019 में पारित किया गया था ।
 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच करने की शक्ति है । इसके पास **राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है** ।
- **कार्य:**
 - आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित **खुफिया सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार करना** ।
 - **आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना** ।
 - **कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हतिधारकों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना** ।
- **जाँच क्षेत्र:**
 - NIA के जाँच के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं । NIA अधिनियम, 2008 की धारा 6 के तहत **राज्य सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जाँच के लिये केंद्र सरकार को सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों का उल्लेख कर सकती है** ।
 - केंद्र सरकार NIA को अपने हिसाब से भारत के भीतर अथवा विदेश में किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच करने का निर्देश दे सकती है ।
 - UAPA तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिये एजेंसी को **केंद्र सरकार की मंजूरी** लेनी होती है ।
 - **वामपंथी उग्रवाद (LWE)** के आतंकी वित्तपोषण से संबंधित मामलों से निपटने के लिये एक विशेष प्रकोष्ठ है । किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच के दौरान NIA उससे जुड़े किसी अन्य अपराध की भी जाँच कर सकती है । अंत में जाँच के बाद मामलों को NIA की विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत किये गए परिवर्तन:

- **भारत के बाहर अपराध:**
 - NIA के पास मूल रूप से भारत के भीतर अपराधों की जाँच करने की शक्ति थी, लेकिन संशोधित अधिनियम **इसे भारत के बाहर किये गए**

अपराधों की जाँच करने की अनुमति देता है, जब तक कयिह अंतरराष्ट्रीय संधियों और शामिल देशों के कानूनों का पालन करता है।

- केंद्र सरकार का मानना है कि अगर कोई अपराध भारत के बाहर किया गया है, लेकिन अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वह NIA को मामले की जाँच करने का निर्देश दे सकती है।

■ कानून का वसिस्त दायरा:

- NIA अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की जाँच NIA कर सकती है।
 - अनुसूची में मूल रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और अपहरण-रोधी अधिनियम, 1982 जैसे अधिनियम शामिल थे।
- संशोधन के साथ NIA अब इससे संबंधित मामलों की भी जाँच कर सकती है:
 - [मानव तस्करी](#)
 - [नकली मुद्रा या बैंक नोट](#)
 - नषिद्धि हथियार
 - [साइबर आतंकवाद](#)
 - वसिफोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराध

■ वशिष न्यायालय:

- अधिनियम, 2008 ने अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिये वशिष न्यायालयों की स्थापना की।
- वर्ष 2019 का संशोधन केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को वशिष न्यायालयों के रूप में नामित करने की अनुमति देता है।
- ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। यदिएक क्षेत्र में कई वशिष न्यायालय मौजूद हैं, तो मामले को सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा सौंपा जाएगा।
- राज्य सरकारें सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को वशिष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती हैं।

सूचीबद्ध अपराध:

- अधिनियम की अनुसूची उन अपराधों की एक सूची निर्दिष्ट करती है जिनकी जाँच के साथ ही NIA द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।
- सूची में शामिल हैं:
 - [वसिफोटक पदार्थ अधिनियम](#)
 - [परमाणु ऊर्जा अधिनियम](#)
 - [गैर-कानूनी गतिविधियाँ \(रोकथाम\) अधिनियम](#)
 - [अपहरण वशिधी अधिनियम](#)
 - [नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी अधिनियमों का दमन](#)
 - [सारक अभसिमय \(आतंकवाद का दमन\) अधिनियम](#)
 - महाद्वीपीय शेलफ अधिनियम पर समुद्री नेविगेशन और नशिचिति प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन
 - सामूहिक वनिाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियाँ नषिद्धि) अधिनियम
 - भारतीय दंड संहिता, शस्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध।
 - [नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट](#)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)